

**Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli**

No---

Dated : 13-4-2015

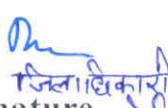
TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.000 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of P.W.D. Gauchar, Uttarakhand for construction of new motor road "Kanchula-Gain" in Chamoli district falls within jurisdiction of Kanchula senz kata village (s) in Karanprayag tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.00 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s)' "Kanchula senz kata , Gain" sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.


Signature
पंजाबी दस्तावेज़

(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE....
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

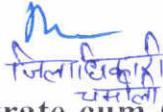
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date **13.04.2015** at time **14:00HRS** at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measure 5.260 hect for the construction of construction of new motor road "Kanchula-Gain" (Proposed Lenth Km 7.200) and forest land 4.000 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanprayag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 13.04.2015


District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत सीनला-मैरुरा भोटर मार्ग से कांचुला
जौन भौं प्रार्ग के नव निर्माण हेतु 1.680 हेतु वन पंचायत, 2.100 हेतु आरक्षि
वन भूमि तथा मन्त्र प्रयोजन इन्हें 0.220 हेतु कुल 4.000 हेतु वन भूमि का लोन नियम
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को दिया गया।

ग्राम पंचायत का नाम जौठला/जौनेली
तहसील कांचुला, जिला वडोदरा,

उत्तराखण्ड में जनपद वडोली के अन्तर्गत सीनला-मैरुरा भोटर मार्ग परियोजना
के निर्माण हेतु (2.100 हेतु आरक्षि वन भूमि, 0.220 हेतु सिविल सोयम भूमि) 1.680 हेतु, तथा मन्त्र प्रयोजन
वन पंचायत भूमि (4.000 हेतु वन भूमि का लोन नियम, 0.220 हेतु जौनेली विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जौठला/जौनेली द्वारा दिनांक 10.3.15 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम पंचायत जौठला/जौनेली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
लोन नियम द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हेतु
ग्राम सचिव



नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

वन अधिकारी वन प्रभाग शोपेश्वर

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ——————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड वन अधिकार समिति परिषेत्र के अन्तर्गत सोनला-ब्रह्मपुरा, मोहर गांव से कालुला डोन ब्राह्मणियोजना के निर्माण हेतु 4,00,000 हो। वन भूमिलों की प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— रुद्रपुर
जनपद— रुद्रपुर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— रुद्रपुर
जनपद— रुद्रपुर

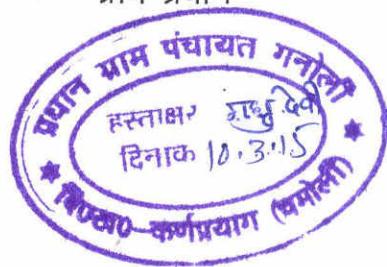
प्रपत्र-23.1

दिनांक 10.3.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जनोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श. गोरेसिंह झुट्टर	गोरेसिंह
2	।। रघुनाथसिंह झुट्टर	रघुनाथ
3	" अहावीरसिंह "	
4	" झुकरासिंह "	झुकरासिंह
5	" अवतारसिंह " (प्रबोधन) जनोली	अवतारसिंह
6	" गोलिंद्र सिंह "	गोलिंद्र
7	ज्व. शुड्डी देवी " (प्रबोधन) जनोली	शुड्डी देवी
8	श. दालासिंह "	दालासिंह
9	" अवरासिंह "	अवरासिंह
10	" अवतारसिंह " (प्रबोधन) जनोली	अवतारसिंह
11	" सरबारसिंह "	सरबारसिंह
12	ज्व. शुड्डी कुमारी देवी (प्रबोधन) जनोली	कुमारी देवी
13	" देवधरी देवी "	देवधरी देवी
14	" शोता देवी " अवधान जनोली	शोता देवी
15	श. बलवत्ता सहू कठ्ठत	बलवत्ता सहू
16	" गणपात्रसिंह "	गणपात्र
17	" जसधानालहू झुट्टर "	जसधानालहू
18	" रमेश्वरसिंह "	रमेश्वरसिंह
19	ज्व. शुड्डी कुसुम देवी "	कुसुम देवी
20	" देवधरी देवी "	देवधरी देवी
21	फालुणी देवी (नाइलदर्य गढ़ 3)	फालुणी देवी
22	श. गवरासिंह कठ्ठत	गवरासिंह
23	" कल्याणसह कठ्ठत	कल्याणसह
24	" बनाट झुट्टर "	बनाट
25	" चन्दनालहू कठ्ठत "	चन्दनालहू

ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हेठो आरक्षित / वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हेठो कुल 4.000 हेठो आरक्षित / वनपंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम-भैंसेन्धा
तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

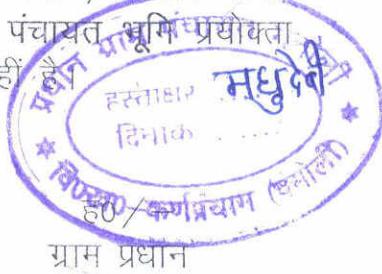
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हेठो आरक्षित / वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हेठो कुल 4.000 हेठो आरक्षित / वनपंचायत भूमि का लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्रामिणजा बहुद्वारा दिनांक ४-५-१२ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काचुला के ग्रामवासियों को ०.६४ हेठो वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हेठो/-
ग्राम सचिव प्रपत्रमानगवाल
ग्रामपंचायती



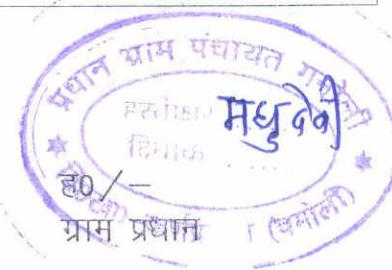
नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक ०८.५.२०७४ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मर्सेलकोटा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बुधनाथ ५८	बुधनाथ ५८
2	अवलाल ५८	अवलाल ५८
3	मुरली ५८	मुरली ५८
4	पुष्टि ५८	पुष्टि ५८
5	ज्येष्ठा ५८	ज्येष्ठा ५८
6	लक्ष्मी ५८	लक्ष्मी ५८
7	गोपी ५८	गोपी ५८
8	दान ५८	दान ५८
9	लिपुपाल ५८	लिपुपाल ५८
10	दशीत ५८	दशीत ५८
11	जोगात ५८	जोगात ५८
12	उम्मीद ५८	उम्मीद ५८
13	जाव ५८	जाव ५८
14	मुकुल ५८	मुकुल ५८
15	जातर ५८	जातर ५८
16	मुख्यन ५८	मुख्यन ५८
17	मुकुल ५८	मुकुल ५८



प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला—कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि�0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम का नाम —**कॉचुला**
तहसील—कर्णप्रयाग, जिला—चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला—कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि�0वि0 गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम **डाला** द्वारा दिनांक **१५.१०.१७.** को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काचुला के ग्रामवासियों को **०.८४ हे0** वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हे0/-
ग्राम सचिव **रुप० एम० नगवाल**
या० पं० वि० अ०



ग्राम प्रधान

नोट :— *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक ०४.५.२०१७ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - जायल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	एमारुड	एमारुड
2	पद्मल	पद्मल
3	दलबीर	दलबीर
4	कुमारुड	कुमारुड
5	बाला	बाला
6	योद्धा	योद्धा
7	दलबीर	दलबीर
8	जाविद	जाविद
9	ब.पटेल	ब.पटेल
10	प्रेम	प्रेम
11	नोहन	नोहन
12	न.गल	न.गल
13	ओवल	ओवल
14	मधुमेह	मधुमेह
15	बिलारुड	बिलारुड
16	दलबीर	दलबीर
17	आवान	आवान



प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला—कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हेठो आरक्षित / वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हेठो कुल 4.000 हेठो आरक्षित / वनपंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम का नाम — कौराठ
तहसील—कर्णप्रयाग, जिला—चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला—कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हेठो आरक्षित / वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हेठो कुल 4.000 हेठो आरक्षित / वनपंचायत भूमि का लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तीत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम कैरींट द्वारा दिनांक 8-5-14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काचुला के ग्रामवासियों को 0.86 हेठो वन पंचायत भूमि-प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हेठो
ग्राम सचिव
प्रपत्र एम० कैरींट
ग्राम पंचायत अधिकारी



नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 06-5-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - लौहा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर:
1-	कुमार अधिकारी वर्मा	कुमार अधिकारी
2-	लखन सिंह वर्मा	लखन सिंह
3-	जगदाधिकारी वर्मा	जगदाधिकारी
4-	वनदहुराधिकारी वर्मा	वनदहुराधिकारी
5-	यशवर्माधिकारी वर्मा	यशवर्माधिकारी
6-	झानवलाधिकारी वर्मा	झानवलाधिकारी
7-	निश्चल सिंह वर्मा	निश्चल सिंह
8-	प्रवाल वर्मा वर्मा	प्रवाल वर्मा
9-	केनवीर अधिकारी वर्मा	केनवीर अधिकारी

